Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

2 नवंबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 11 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कोरवेट हेतु जीआरएसई और जीएसएल के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

MoD signs Rs 53,866.50 crore contracts with GRSE and GSL for eight Next Generation Corvettes for the Indian Navy

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कोरवेट (एनजीसी) की खरीद हेतु गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। अनुबंधों के तहत जीआरएसई पांच कोरवेट का निर्माण करेगी, जबकि जीएसएल शेष तीन का निर्माण करेगी। मंत्रालय के अनुसार यह पहली परियोजना है जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जाएगा और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा निर्मित किया जाएगा। उन्नत मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सूट से लैस एनजीसी वायु, सतह और जलमग्न क्षेत्रों में मिशन को अंजाम दे सकेंगे, जिनमें समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध अभियान, तटीय रक्षा, तटीय (लिटोरल) युद्ध अभियान और समुद्री उपस्थिति एवं निगरानी मिशन शामिल हैं। इन जहाजों के निर्माण से अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों तथा एमएसएमई में 460 लाख व्यक्ति-दिवस का रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। पणजी से जारी PIB की एक अलग रिलीज़ के अनुसार सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जीएसएल ने तीन कोरवेट के निर्माण का काम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया, और एनजीसी परियोजना जीएसएल के इतिहास में उसे मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331418

2 भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेष तवांग मठ पहुंचे; तवांग, बोमडिला और नामसाई में होगी प्रदर्शनी

Sacred Piprahwa relics of Lord Buddha arrive at Tawang Monastery; exposition to travel across Tawang, Bomdila and Namsai

SSC • Railway • General

संस्कृति मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को बताया कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से लाए गए शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने 31 अक्टूबर 2026 को तवांग में औपचारिक रूप से प्राप्त किया, और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में ऐतिहासिक गादेन नामग्याल ल्हात्से (तवांग मठ) में उनका पारंपरिक धार्मिक स्वागत किया गया। संस्कृति मंत्रालय यह प्रदर्शनी अरुणाचल प्रदेश सरकार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) और राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ मिलकर बौद्ध आस्था के तीन केंद्रों में आयोजित कर रहा है: 1 से 7 नवंबर तक तवांग मठ में, 8 से 13 नवंबर तक टीजीएल मठ (लोअर गोम्पा), बोमडिला में और 14 से 20 नवंबर 2026 तक गोल्डन पैगोडा, नामसाई में; पवित्र अवशेष 21 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय संग्रहालय वापस लाए जाएंगे। ये अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपराहवा से हैं, जो प्राचीन कपिलवस्तु और भगवान बुद्ध की शाक्य परंपरा से जुड़ा एक पुरातात्विक स्थल है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सदी से भी अधिक समय बाद पवित्र पिपराहवा अवशेषों की घर वापसी को गर्व और खुशी का पल बताया। यह प्रदर्शनी ल्हाबाब दुचेन के अवसर पर हो रही है, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा में बुद्ध के स्वर्गलोक से अवतरण की स्मृति में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। साथ में लगी प्रदर्शनी 'पवित्र पिपराहवा की खोज: पवित्र बुद्ध अवशेषों और उनकी खोज की कहानी' (Unearthing the Sacred Piprahwa: The Story of the Holy Buddha Relics and Their Discovery) में पिपराहवा में हुई पुरातात्विक खोजों का इतिहास और भारत में इसकी वापसी सहित पिपराहवा विरासत की यात्रा प्रस्तुत की जाएगी, और आईबीसी अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 2 नवंबर 2026 को तवांग के कलावांगपो सम्मेलन कक्ष में 'बौद्ध धर्म: हिमालयी क्षेत्र और उससे आगे प्रसार' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331377

3 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए: 7 कार्य दिवसों में जांच, 15 दिनों में निवारण

Rural Development Ministry notifies VB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026: enquiry within 7 working days, resolution within 15 days

SSC • Banking • General

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को बताया कि उसने विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी - शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जिनसे योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के लिए एक सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय और समयबद्ध व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्य सरकारें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर यह व्यवस्था स्थापित करेंगी, जहाँ नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे; जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी करेंगे। कोई भी व्यक्ति नामित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, डिलीवरी के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट से, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, या टेलीफोन, निर्धारित हेल्पलाइन अथवा राज्य सरकार द्वारा तय किसी अन्य माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों को उसी दिन, और ऐसा संभव न हो तो अगले कार्य दिवस तक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पंजीकृत करना होगा, और शिकायतकर्ता को पंजीकरण संख्या, शिकायत प्राप्ति की तारीख और शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी के पदनाम वाली पावती दी जाएगी। शिकायत के प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर उसका पंजीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर जांच पूरी करनी होगी और 15 दिनों के भीतर उसका निवारण करना होगा; 15 दिनों में न सुलझी शिकायत अगले उच्च स्तर पर भेजी जाएगी और समाधान होने तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जारी रहेगी। शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार दायर और निस्तारित की जाएगी।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331390

4 सिक्किम का सोरेंग पीएमएमएसवाई के अंतर्गत देश का पहला अधिसूचित जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर; पूर्वोत्तर में मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणीकरण के लिए एसओपी का शुभारंभ

Soreng, Sikkim is India's first notified organic fisheries cluster under PMMSY; SOP for organic certification of fisheries in the North-East launched

SSC • Banking • Railway • General

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्य पालन विकास पहलों की समीक्षा के लिए 2 नवंबर 2026 को सिक्किम के मंगन जिले का दौरा किया; यह दौरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों की आवधिक यात्राओं के लिए बनाए गए संरचित तंत्र के अनुरूप था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का शुभारंभ किया और पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 375 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें हैचरी, फीड मिल और कोल्ड स्टोरेज जैसी मत्स्य पालन अवसंरचना तथा बायोफ्लॉक और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) जैसी उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए, मुख्यमंत्री मत्स्य उत्थान योजना (एमएमएमयूवाई) के अंतर्गत पांच मछली किसानों को चेक दिए गए, और दो मत्स्य सहकारी समितियों के 15 मत्स्य किसानों को मछली चारा वितरित किया गया। मंत्रालय ने बताया कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत देश भर में 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें सिक्किम और मेघालय के जैविक मत्स्य क्लस्टर शामिल हैं, और सिक्किम का सोरेंग जिला पीएमएमएसवाई के अंतर्गत देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है; यह क्लस्टर हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक दवाओं और कीटनाशकों के बिना पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मछली पालन पर केंद्रित है, जिसमें अमूर कार्प, इंडियन मेजर कार्प (आईएमसी) और ट्राउट पर विशेष जोर है। एसओपी का उद्देश्य जैविक उत्पादन के लिए एक संरचित ढांचा देना और मूल्य श्रृंखला में ट्रेसबिलिटी (पता लगाने की क्षमता) को समर्थन देना है। सिक्किम ने स्थानीय रूप से उत्पादित रेनबो ट्राउट की संस्थागत खरीद के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331541

5 डॉ. जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ में नई भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया; वर्ष 2027 में चार और डॉप्लर मौसम रडार चालू किए जाएंगे

Dr Jitendra Singh inaugurates a new seismological observatory at Kishtwar; four more Doppler Weather Radars to be commissioned in 2027

SSC • Railway • Science • General

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2 नवंबर 2026 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के उच्च भूकंपीय क्षेत्र में नई भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक डिजिटल भूकंपीय उपकरणों से सुसज्जित यह वेधशाला वास्तविक समय में आंकड़े नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के भूकंप निगरानी केंद्र को भेजेगी; इसके साथ जम्मू-कश्मीर में अब चार भूकंपीय वेधशालाएं हैं - जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर और किश्तवाड़ में। मंत्री ने बताया कि पहले इस क्षेत्र में डॉप्लर मौसम रडार की कोई सुविधा नहीं थी, वर्ष 2014 के बाद बनिहाल, जोत, जम्मू और श्रीनगर में चार डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किए गए हैं, और वर्ष 2027 में डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग और बारामूला में चार और डॉप्लर मौसम रडार चालू किए जाने हैं। पहले उधमपुर, कठुआ और रामबन में तीन स्वचालित मौसम केंद्र थे; नौ और केंद्र स्थापित किए जाने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है, और इनमें किश्तवाड़ में चार, डोडा और रामबन में दो-दो और कठुआ में एक केंद्र शामिल है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पांच जिलों में वर्षामापी केंद्रों की संख्या नौ से बढ़कर 15 हो गई है, इन पांच जिलों की सभी पंचायतों में पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि-मौसम परामर्श सेवाओं का लाभ 5,467 लाभार्थियों तक पहुंचा है। उन्होंने पटनीटॉप स्थित हाई-एल्टीट्यूड क्लाउड भौतिकी प्रयोगशाला और जम्मू में स्थापित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का भी उल्लेख किया, और नागरिकों से मौसम संबंधी वैज्ञानिक चेतावनियों के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा, 'जानकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस जानकारी के अनुसार कार्रवाई करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।'

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331574

6 गृह मंत्रालय: देश में FRRO कार्यालयों की संख्या बढ़कर 20 हुई; अमित शाह ने वर्ष 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में FRRO स्थापित करने का निर्देश दिया

MHA: FRRO offices in the country now 20; Amit Shah directs FRROs in all state capitals by 2027

SSC • Railway • General

गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) स्थापित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पर्यटन, चिकित्सा और शिक्षा के लिए भारत आने वाले विदेशियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 से पांच नए FRRO स्थापित किए गए हैं: वर्ष 2025 में जयपुर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी (जो पहले क्रमशः दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता स्थित FRRO के अधिकार क्षेत्र में थे), और वर्ष 2026 में आइजोल (मिजोरम) और अमरावती (आंध्र प्रदेश) (जो पहले क्रमशः FRRO कोलकाता और FRRO हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में थे)। हाल ही में कोहिमा (नगालैंड), अगरतला (त्रिपुरा) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में तीन नए FRRO कार्यालय अधिसूचित किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में FRRO कार्यालयों की कुल संख्या अब बढ़कर 20 हो गई है, और सरकार शेष राज्यों में भी FRRO स्थापित करने पर काम कर रही है। इमिग्रेशन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025), जिसने इमिग्रेशन और विदेशियों से संबंधित चार पूर्ववर्ती कानूनों को समेकित किया है, विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने, आवागमन और प्रस्थान के विनियमन के लिए एक एकीकृत वैधानिक ढांचा प्रदान करता है; इसके अनुसार इमिग्रेशन ब्यूरो को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अन्य के साथ-साथ, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) से सहायता मिलेगी। FRRO पात्र श्रेणी के विदेशियों का आगमन के बाद पंजीकरण करता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)/आवासीय परमिट जारी करता है, विदेशी के विवरणों में हुए परिवर्तन दर्ज करता है, संरक्षित एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा की अनुमति देता है और निकास परमिट जारी करता है; e-FRRO के जरिए 35 ऑनलाइन सेवाएं पंजीकरण, वीजा विस्तार, रूपांतरण तथा अन्य पात्र इमिग्रेशन संबंधी सेवाओं की सुविधा देती हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331564

7 ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए; अपील दायर करने की समय-सीमा 30 दिन से घटकर 15 दिन

TRAI issues Telecom Consumers Complaint Redressal (Fourth Amendment) Regulations, 2026; time limit for filing an appeal cut from 30 days to 15 days

SSC • Banking • General

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 2 नवंबर 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए। इससे पहले 7 मई 2026 को मसौदे पर परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिस पर हितधारकों से 32 टिप्पणियां और 24 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, और 17 जुलाई 2026 को ऑनलाइन खुली चर्चा (ओपन हाउस डिस्कशन) हुई। संशोधित विनियम उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे जिनके पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन दस हज़ार से अधिक ग्राहक हों; 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक वित्तीय टर्नओवर पर आधारित मौजूदा वैकल्पिक मानदंड हटा दिया गया है। उपभोक्ता अब शिकायत केंद्र, वेबसाइट और वेब पोर्टल के अलावा सेवा प्रदाता के मोबाइल एप्लिकेशन से भी शिकायत और अपील दर्ज कर सकेंगे, सेवा अनुरोध कर सकेंगे और सेवा संबंधी प्रश्न पूछ सकेंगे। शिकायत केंद्रों पर उपभोक्ता सहायता मौजूदा 16 घंटे की व्यवस्था के बजाय सप्ताह के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी; यह सहायता मानव प्रतिनिधियों, स्वचालित प्रणालियों, अन्य ग्राहक-केंद्रित तकनीकी समाधानों या इनके संयोजन से दी जा सकती है, पर मानवीय सहायता प्रतिदिन कम से कम सोलह घंटे उपलब्ध रहेगी; दिव्यांगजनों की कॉल प्राप्त करने के लिए समर्पित डेस्क या हेल्पलाइन रखनी होगी। शिकायत के निपटारे के बाद अपील दायर करने की समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है, और सेवा प्रदाता के प्रबंधन के नियमित कर्मचारियों में से कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाले एक या अधिक व्यक्तियों से बने अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्णय बताना होगा; सलाहकार समिति के माध्यम से अपीलों के निपटारे की पुरानी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। नए प्रावधानों में शिकायत या अपील के निपटारे या बंद होने पर पांच-बिंदु पैमाने पर ऑनलाइन फीडबैक सर्वेक्षण और उसके परिणामों का त्रैमासिक प्रकाशन, सीईओ या निदेशक मंडल के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट, हर सेवा प्रदाता में उपभोक्ता शिकायत निवारण निगरानी समिति (जिसकी बैठक साल में कम से कम एक बार होगी), ट्राई द्वारा आवधिक नियामक समीक्षा, तथा ऑडिट, निरीक्षण, विश्लेषण या समीक्षा के दौरान विनियमों का उल्लंघन करके शिकायत या अपील निपटाए जाने के मामलों और त्रैमासिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट जमा न करने या देर से जमा करने पर वित्तीय हतोत्साहन (फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव) शामिल हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331704

8 प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026' का उद्घाटन किया; आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नौवीं सभा के साथ

PM inaugurates Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 at Bharat Mandapam; summit coincides with the Ninth Assembly of the International Solar Alliance

SSC • Banking • General

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026' (Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का शिखर सम्मेलन वैश्विक ऊर्जा झटकों के बीच हो रहा है और इसका दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नौवीं सभा के साथ हो रहा है और इसमें हरित हाइड्रोजन पर चौथे सम्मेलन के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 'ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में ही निहित है' कहते हुए उन्होंने स्टार्टअप्स, आईआईटी, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों से ऐसे सौर मॉडल विकसित करने का आग्रह किया जो चौबीसों घंटे और हर मौसम में काम कर सकें और घरों की अधिकांश जरूरतें पूरी कर सकें, जैसे छत पर सौर ऊर्जा से खाना पकाना (रूफटॉप सोलर कुकिंग) और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों व कारों के लिए होम सोलर चार्जिंग। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5,000 मेगावाट की तैरने वाली (फ्लोटिंग) सौर क्षमता विकसित की जाएगी, और हाल ही में 1.86 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III' (Green Energy Corridor Phase-III) को मंजूरी दी है। श्री जोशी के अनुसार भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता, जो सितंबर 2024 में 200 गीगावाट से अधिक हो गई थी, अब 310 गीगावाट तक पहुँच गई है, और 'पीएम सूर्य घर' के तहत 65 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरित हाइड्रोजन की खरीद प्रतिबद्धताओं (ऑफटेक कमिटमेंट) के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, और दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा, 'भारत में निवेश करें। भारत में नवाचार करें। भारत के साथ आगे बढ़ें।'

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331789

9 एमएसडीई ने ग्रीन चैनल के माध्यम से 19 संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई-स्किल्स) के रूप में पैनलबद्ध किया; मान्यता 8 अक्टूबर 2029 तक वैध

MSDE empanels 19 institutions as Centres of Excellence-Skills through the Green Channel; recognition valid till 8 October 2029

SSC • Railway • General

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 2 नवंबर 2026 को 19 प्रतिष्ठित संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई-स्किल्स) के रूप में औपचारिक मान्यता दी; नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित समारोह में एमएसडीई की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। यह मान्यता 9 अक्टूबर 2026 से 8 अक्टूबर 2029 तक वैध है। इन संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के पैनलबद्धीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत उपलब्ध ग्रीन चैनल के माध्यम से पैनलबद्ध किया गया है। यह स्थापित प्रतिष्ठा वाले पात्र संस्थानों के लिए त्वरित मार्ग है, जिनमें राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान, पीएम-सेतु के तहत उन्नत किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित या पैनलबद्ध कौशल उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं; इनके आवेदन नामांकन या नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के बिना सीधे कार्यकारी समिति के समक्ष विचार के लिए रखे जाते हैं। ये दिशा-निर्देश 15 जुलाई 2026 को विश्व युवा कौशल दिवस समारोह के दौरान कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने जारी किए थे। कौशल उत्कृष्टता केंद्र की परिकल्पना एक स्थायी, उन्नत और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र के रूप में की गई है; इसके कार्यों में उन्नत एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशिक्षण, मूल्यांकन, मार्गदर्शन और करिअर परामर्श, प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकन-कर्ताओं का प्रशिक्षण, उद्योग जगत के साथ जुड़ाव तथा प्रशिक्षण के बाद के परिणामों की उपलब्धि और निगरानी शामिल हो सकते हैं, और इसका पैनलबद्धीकरण किसी विशेष योजना से बंधा नहीं है। मान्यता पाने वाले संस्थान नवीकरणीय ऊर्जा (आईआईटी रुड़की का जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और चेन्नई तथा कायथार स्थित राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान सहित), रसायन एवं पेट्रोरसायन (गुवाहाटी, संभाजीनगर, लखनऊ, कोच्चि और भुवनेश्वर स्थित सीआईपीईटी केंद्र), निर्माण (भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, पुणे), बहु-क्षेत्रीय, लौह एवं इस्पात, समुद्री इंजीनियरिंग (आईएनएस शिवाजी, पुणे), पर्यटन एवं आतिथ्य और कृषि (राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद) क्षेत्रों से हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331775

10 कोयला मंत्रालय के वित्त वर्ष 2024-25 के स्टार रेटिंग पुरस्कार रायपुर में: 50 कोयला खदानों को फाइव-स्टार रेटिंग

Ministry of Coal's Star Rating awards for FY 2024-25 in Raipur: 50 coal mines receive Five-Star Ratings

SSC • Banking • General

कोयला मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत के कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्र में उत्कृष्टता को सराहा गया; समारोह की शोभा कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने बढ़ाई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 50 कोयला खदानों को फाइव-स्टार रेटिंग मिली; इनमें से 10 खदानों ने अपनी-अपनी श्रेणियों में 93 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओपनकास्ट (खुली खदान) श्रेणी में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और एनटीपीसी ने तथा अंडरग्राउंड (भूमिगत) श्रेणी में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक फाइव-स्टार रेटिंग वाली खदानों के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) को विशेष सराहना मिली, जबकि स्टार रेटिंग मूल्यांकन के साथ-साथ उत्पादन में भी लगातार उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए एनसीएल और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की सराहना की गई। राज्य मंत्री ने स्टार रेटिंग कार्यक्रम को कोयला खदानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया, कोयला कंपनियों से इसे आत्म-मूल्यांकन, सीखने और सुधार के अवसर के रूप में देखने को कहा, और वित्त वर्ष 2025-26 के स्टार रेटिंग कार्यक्रम में व्यापक और अधिक सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अपने स्वागत भाषण में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) के कोयला नियंत्रक श्री सतीश कुमार ने कहा कि यह समारोह सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, वैज्ञानिक खनन प्रथाओं, उत्पादकता और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में खदानों के अनुकरणीय प्रदर्शन को पहचानने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331780

11 दस महीने का ट्रांसओशनिक नौकायन अभियान लोकायन 26 पूरा कर आईएनएस सुदर्शिनी कोच्चि लौटा

INS Sudarshini returns to Kochi after completing Lokayan 26, a ten-month transoceanic sailing expedition

SSC • Railway • Defence • General

भारतीय नौसेना ने 2 नवंबर 2026 को आईएनएस सुदर्शिनी का औपचारिक स्वागत किया, जब यह जहाज 22,000 नॉटिकल मील से अधिक के दस महीने के ट्रांसओशनिक (अंतर-महासागरीय) नौकायन अभियान लोकायन 26 को सफलतापूर्वक पूरा करके कोच्चि लौटा; वापसी पर वॉटर कैनन से सलामी दी गई और नौसेना बैंड ने औपचारिक स्वागत किया। फ्लैग-इन समारोह की अध्यक्षता दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने की। 20 जनवरी 2026 को कोच्चि से रवाना हुई इस यात्रा में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के 11 देशों में 17 अलग-अलग बंदरगाहों पर पड़ाव (पोर्ट कॉल) और दो बार अटलांटिक महासागर पार करना शामिल रहा। अभियान की प्रमुख झलकियों में फ्रांस में एस्केल ए सेट (Escale à Sète) समुद्री विरासत महोत्सव तथा अमेरिका में स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के तहत सेल 250 (SAIL 250) और अंतरराष्ट्रीय नौसेना समीक्षा (International Naval Review) में जहाज की भागीदारी शामिल रही। नौसेना के अनुसार, चुनौतीपूर्ण मौसम और समुद्री परिस्थितियों के बीच 19 दिनों में 2,200 नॉटिकल मील की एक अटलांटिक पार यात्रा पूरी तरह पालों के सहारे तय की गई सबसे लंबी दूरी रही। चालक दल ने रॉयल मोरक्कन नौसेना, पुर्तगाली नौसेना, इतालवी नौसेना, मिस्र की नौसेना और स्पेनिश नौसेना के साथ पेशेवर संवाद, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और क्रॉस-ट्रेनिंग गतिविधियां कीं। नौसेना ने कहा कि यह तैनाती भारत के समुद्री विजन महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाती है, और इसका मुख्य उद्देश्य युवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को पाल प्रशिक्षण (सेल ट्रेनिंग) देना रहा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331798

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार सिक्किम का कौन-सा जिला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है?

(A) गंगटोक
(B) सोरेंग
(C) नामची
(D) मंगन

प्र.2 2 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आठ नेक्स्ट जेनरेशन कोरवेट के लिए हस्ताक्षरित 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों के तहत कौन-सा शिपयार्ड तीन कोरवेट का निर्माण करेगा, जबकि दूसरा शिपयार्ड पांच कोरवेट बनाएगा?

(A) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
(B) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(C) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
(D) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स

प्र.3 कोयला मंत्रालय के वित्त वर्ष 2024-25 के स्टार रेटिंग पुरस्कारों में कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक फाइव-स्टार रेटिंग वाली खदानों के लिए किस कंपनी को विशेष सराहना मिली?

(A) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(B) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(C) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
(D) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्र.4 गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस वर्ष तक सभी राज्यों की राजधानियों में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) स्थापित करने का निर्देश दिया है?

(A) 2027
(B) 2030
(C) 2028
(D) 2026

प्र.5 ट्राई के दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 के तहत शिकायत के निपटारे के बाद अपील दायर करने की समय-सीमा कितने दिन कर दी गई है?

(A) 60 दिन
(B) 45 दिन
(C) 15 दिन
(D) 30 दिन

उत्तर: 1-(B) 2-(A) 3-(A) 4-(A) 5-(C)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।